*ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं में संवृद्धि और विकास**

माइकल देबब्रत पात्र

ब्रिक्स: ऐक्रनिम से लेकर वैश्विक आर्थिक महाशक्ति तक[1]

प्रोफेसर पामी दुआ, निदेशक, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रो. योगेश सिंह, कुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय, प्रो. संघमित्रा बंद्योपाध्याय, निदेशक, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, दिल्ली केंद्र, प्रो. चेतन घाटे, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, विशिष्ट आमंत्रित अतिथिगण और सम्मेलन प्रतिभागियों, मैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और भारतीय सांख्यिकी संस्थान, दिल्ली केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 'ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं में संवृद्धि और विकास' विषय पर आयोजित इस सम्मेलन के उद्घाटन भाषण देने के लिए आमंत्रित किए जाने के लिए सम्मानित महसूस कर रहा हूं। भारत द्वारा वर्ष 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालने के मद्देनजर यह सम्मेलन सामयिक और प्रासंगिक है। सम्मेलन में चर्चा और प्रस्तुत किए जाने वाले हस्ताक्षरित पेपर निश्चित रूप से इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं ने महामारी के दौरान और महामारी के बाद के दिनों में अपनी प्रगति की रूपरेखा कैसे तैयार की है। मेरा संबोधन दो भागों में बंटा हुआ है, हालांकि मैं अंतर-संबंधों को बताने के लिए आगे-पीछे हो सकता हूं। पहला भाग ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं की स्थिति और उनके समक्ष आने वाली तात्कालिक चुनौतियों से निपटने के बारे में होगा। इसके बाद, ब्रिक्स की वर्तमान अध्यक्षता को देखते हुए भारत के सामने आने वाली चुनौतियों का अवलोकन किया जाएगा।

वैश्विक अर्थव्यवस्था में ब्रिक्स

संक्षिप्त नाम ब्रिक का पता 2001 में चला और व्यापक रूप से इसका श्रेय जिम ओ'नील को दिया गया, जो उस समय गोल्डमैन सैक्स एसेट मैनेजमेंट के अध्यक्ष थे, लेकिन जाहिर तौर पर इसकी उत्पत्ति के बारे में कुछ विवाद है। जो भी हो, ब्रिक यानी ब्राजील, रूस, भारत और चीन, की पहली औपचारिक बैठक, 2009 में येकातेरिनबर्ग, रूस में हुई थी जिसमें उनके नेताओं ने प्रतिनिधित्व किया था। दक्षिण अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ और यह ब्रिक्स हो गया। एक साथ मिलकर, ब्रिक्स दुनिया की आबादी का 40 प्रतिशत से अधिक, वैश्विक जीडीपी का एक चौथाई, वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का एक चौथाई और विश्व व्यापार का पांचवां हिस्सा है। इसी संदर्भ में ब्रिक्स को एक उभरता हुआ वैश्विक महाशक्ति माना जा रहा है।

ब्रिक्स में व्यापक विविधता के साथ-साथ विशिष्ट समानताएं भी शामिल हैं। इनमें सबसे अधिक आबादी वाले देशों के साथ-साथ अपेक्षाकृत कम रहने वाले लोग शामिल हैं, विभिन्न जनसांख्यिकीय प्रोफाइल के साथ, विशेष रूप से जनसंख्या उम्र बढ़ने, जीवन प्रत्याशा और आश्रितों की हिस्सेदारी के मामले में। वे अपने वित्तीय विकास के मामले में भी काफी व्यापक रूप से भिन्न हैं, बैंक खातों के स्वामित्व वाले वयस्कों के अनुपात को वित्तीय समावेशन के उपाय के रूप में माना जाता है। ब्रिक्स में कई समान विशेषताएं भी हैं - विकास के मोटे तौर पर समान चरण; विकास रणनीति के रूप में स्थायी तरीके से संवृद्धि में तेजी लाना; समावेशिता और डिजिटलीकरण पर जोर; और जलवायु लचीलापन में निवेश करना। इन्हीं विशेषताओं के साथ ब्रिक्स पूरी दुनिया में मानव समाजों के विकास और समृद्धि में योगदान करने के लिए एक साथ आए हैं और इस तरह वैश्विक सामान्य भलाई के लिए काम करेंगे।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने वैश्विक जीडीपी को वर्ष 2020 में 3.1 प्रतिशत की अभूतपूर्व गिरावट और वर्ष 2021 में 5.9 प्रतिशत तक विस्तार होने का पूर्वानुमान किया है। ब्रिक्स को वैश्विक सुधार का सबसे महत्वपूर्ण इंजन होने की उम्मीद है, जिसमें वर्ष 2021 में वैश्विक संवृद्धि का 42 प्रतिशत का योगदान है, जो अगले तीन संवृद्धि वाहकों (यूएस; यूरो क्षेत्र; यूके) की संयुक्त हिस्सेदारी से अधिक है। ब्रिक्स विश्व व्यापार में भी एक जबरदस्त

---

* दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (डीएसई) और भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आईएसआई), दिल्ली द्वारा 'ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं में संवृद्धि और विकास' विषय पर आयोजित सम्मेलन में भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर माइकल देबब्रत पात्र द्वारा दिया गया मुख्य भाषण।

[1] दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (डीएसई) और भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आईएसआई), दिल्ली ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी इनिशिएटिव के तत्वावधान में, 12 नवंबर 2021 को। महुआ रॉय, सितिकंठ पट्टनायक, स्मिता शर्मा, आशीष थॉमस जॉर्ज, हरेंद्र बेहरा, अजेश पी., सार्थक गुलाटी, कुणाल प्रियदर्शी और दुर्गेश पवार की बहुमूल्य टिप्पणियाँ, और विनीत कुमार श्रीवास्तव एवं समीर रंजन बेहरा के संपादकीय सहयोग के लिए आभारी हैं।

ताकत है, जिसकी मूल्य के आधार पर विश्व व्यापार और सेवाओं के व्यापार का लगभग 16 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इनमें कमोडिटी निर्यातक और आयातक दोनों शामिल हैं, जो विनिर्माण और सेवाओं की एक श्रृंखला में देश की विशेषज्ञता के साथ हैं। अंतर-ब्रिक्स व्यापार में मजबूती से विस्तार हो रहा है और इसने महामारी रोधी के एक स्तर का प्रदर्शन किया है - उदाहरण के लिए, ब्रिक्स भागीदारों के साथ भारत का व्यापार महामारी वित्तीय वर्ष 2020-21 (अप्रैल-मार्च) में बढ़कर 113.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जो महामारी पूर्व वर्ष 2019-20 के 110 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक था। वर्ष 2021-22 में अब तक, सभी ब्रिक्स राष्ट्र मजबूत निर्यात प्रदर्शन कर रहे हैं।

ब्रिक्स राष्ट्र आर्थिक रूप से खुली अर्थव्यवस्थाएं हैं और पूंजी प्रवाह के लिए पसंदीदा जगह हैं। हाल के वर्षों में, उन्होंने अचानक बंद होने और पोर्टफोलियो प्रवाह के कारण उलटफेर का भी अनुभव किया है। इसके विपरीत, ये सभी अपेक्षाकृत स्थिर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ़डीआई) के प्राप्तकर्ता भी हैं। वर्ष 2020 में, उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में पूंजी प्रवाह में कटौती हुई थी। ब्रिक्स में, केवल भारत और दक्षिण अफ्रीका निवल बहिर्वाह से बचे हुए थे। वर्ष 2021 में अब तक निवल पूंजी प्रवाह भारत और ब्राजील के पक्ष में बना रहा। वर्ष 2013 के टेंपर टैंट्रम के समय की स्थिति के विपरीत, ब्रिक्स बाहरी मोर्चे पर अच्छी तरह से मजबूत प्रतीत होता है। वर्तमान में, ब्रिक्स के पास वैश्विक विदेशी मुद्रा भंडार का 33 प्रतिशत हिस्सा है, जिसमें चीन, भारत और रूस दुनिया के शीर्ष दस आरक्षित निधि धारकों में शामिल हैं। संभावित आयात कवर द्वारा मापी गई आरक्षित पर्याप्तता 7 से 19 महीनों के बीच होती है। चीन और रूस आम तौर पर चालू खाता अधिशेष चलाते हैं, और इसलिए वित्तीय बाजारों का ध्यान आमतौर पर ब्रिक्स चालू खाता घाटे वाली अर्थव्यवस्थाओं - ब्राजील, भारत और दक्षिण अफ्रीका पर होता है। भारत अब तक वर्ष 2020 और वर्ष 2021 में मामूली चालू खाता अधिशेष में चला गया है, लेकिन यह बढ़ती आयात मांग को देखते हुए नहीं रह सकता है।

बहुपक्षीय भूमिका में ब्रिक्स

ब्रिक्स बहुपक्षवाद के कट्टर समर्थक रहे हैं, आईएमएफ में कोटा और शासन सुधारों के लिए सर्वसम्मति से मतदान करते हैं ताकि इसे वैश्विक आर्थिक वास्तविकताओं का अधिक प्रतिनिधि बनाया जा सके, विशेष रूप से ईएमई की बढ़ती प्रोफ़ाइल जो देखते हुए। साथ में, उनके पास आईएमएफ के कोटा संसाधनों का 14.8 प्रतिशत है जो कुल एसडीआर 476.4 बिलियन और मतदान शक्ति का 14 प्रतिशत है। विश्व बैंक में, उन्होंने संस्था की पूंजी में अपना हिस्सा बढ़ाकर 14.1 प्रतिशत कर दिया है, जिसमें मतदान शक्ति में 13.4 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। एक प्रतिकूल और अस्थिर अंतरराष्ट्रीय वातावरण के बीच भविष्य के कोटा सुधार में गतिरोध का सामना करते हुए, ब्रिक्स ने अपने कोटा संसाधनों के पूरक के लिए आईएमएफ को लेनदार बना दिया है। आईएमएफ की उधार लेने की नई व्यवस्था (एनएबी) में ब्रिक्स का सामूहिक हिस्सा कुल एसडीआर 361 बिलियन का 16 प्रतिशत है। इसके अलावा, प्रत्येक ब्रिक्स राष्ट्र ने आईएमएफ के साथ द्विपक्षीय उधार व्यवस्था (बीबीए) पर हस्ताक्षर किए हैं, जो कुल एसडीआर 135 बिलियन के 17 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। इसके अलावा, ब्रिक्स ने एक आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था या सीआरए के तहत 100 बिलियन अमरीकी डालर की स्वैप की व्यवस्था की है, जो आईएमएफ कोटा में उनके संयुक्त हिस्से से मेल खाता है और इसे ग्लोबल फाइनेंशियल सेफ़्टी नेट (जीएफएसएन) के एक हिस्से के रूप में गिना जाता है।

ब्रिक्स महामारी से गंभीर रूप से प्रभावित हुआ था, जिसमें संक्रमण की कई लहरें थीं, जो अब भी जान ले रही हैं। कुल संक्रमणों के मामले में, तीन ब्रिक्स, अर्थात, भारत, ब्राजील और रूस दुनिया के शीर्ष पांच प्रभावित देशों में शामिल हैं। सात दिनों के रोलिंग औसत के संदर्भ में, रूस को छोड़कर सभी ब्रिक्स देशों में नए संक्रमणों में कमी आई है, जिसमें टीकाकरण अभियान के पैमाने और गति शामिल हैं। टीकाकरण के मामले में, हालांकि, चीन में तीन चौथाई आबादी को पूरी तरह से टीका लगाया जा रहा है और दक्षिण अफ्रीका में केवल पांचवां हिस्सा है। पूर्ण टीकाकरण सभी ब्रिक्स देशों के लिए एक तात्कालिक चुनौती है। टीकों के प्रमुख निर्यातकों में चीन, रूस और भारत का प्रमुख स्थान है। भारत के मामले में, घरेलू संक्रमण बढ़ने पर टीके का निर्यात अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। जैसे ही संक्रमण कम हुआ, भारत ने अक्टूबर से टीकों का निर्यात फिर से शुरू कर दिया है, जिसमें क्वाड पहल भी शामिल है। वर्ष 2022 के अंत तक भारत-प्रशांत क्षेत्र के लिए टीकों की कम से कम 1 बिलियन खुराक का

उत्पादन करने की क्वाड पहल के तहत, भारत में अमेरिकी वित्तपोषण क्षमता विस्तार के साथ टीकों का उत्पादन किया जाएगा, जिसमें जापान भारत और ऑस्ट्रेलिया को रियायती ऋण प्रदान करेगा और अंतिम छोर तक डिलिवरी समर्थन देगा। क्वाड पहल के प्रति प्रतिबद्धता की दृढ़ता दर्शाते हुए, भारत ने अक्टूबर में 1 मिलियन खुराक की पहली खेप का 50 प्रतिशत वित्तपोषित किया।

समष्टि-आर्थिक विकास और नीतिगत प्रतिक्रियाएं

संक्रमण और टीकाकरण में अंतर के साथ-साथ मौद्रिक और राजकोषीय नीति समर्थन में अंतर के परिणामस्वरूप, ब्रिक्स को समष्टि-आर्थिक स्थितियों में भिन्नता का सामना करना पड़ रहा है। जहां चीन की रिकवरी तेज और मजबूत रही है, वहीं अन्य ब्रिक्स वर्ष 2021 की दूसरी तिमाही के बाद से धनात्मक संवृद्धि क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। व्यापक अंतर मुद्रास्फीति के परिणामों की विशेषता बताता है। जहां ब्राजील और रूस - दोनों वस्तु निर्यातक - लक्ष्य और सहनशीलता के स्तर से बहुत अधिक मुद्रास्फीति दर का अनुभव कर रहे हैं, वहीं चीन ने उच्च उत्पादक मूल्य मुद्रास्फीति के बावजूद खुदरा मुद्रास्फीति को कम रखा है। दक्षिण अफ्रीका में मुद्रास्फीति लक्ष्य सीमा के भीतर है। भारत में, मुद्रास्फीति मई में ऊपरी सहनशीलता बैंड को पार कर गयी, लेकिन आयात और बफर स्टॉक के साथ-साथ उत्पादकता को प्रोत्साहित करने के उपायों के रूप में मजबूत आपूर्ति पक्ष उपायों के परिणाम मिले हैं, जिससे सितंबर और अक्टूबर 2021 में मुद्रास्फीति लक्ष्य के करीब आ गई है।

ब्रिक्स देशों में उनके मौद्रिक नीति ढांचे के संदर्भ में काफी समानता है। उनमें से चार ने मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण अपनाया है। संख्यात्मक लक्ष्य लगभग चार प्रतिशत हैं और उन सभी में रूस को छोड़कर सहिष्णुता बैंड हैं, जिसका उद्देश्य मुद्रास्फीति को चार प्रतिशत के करीब रखना है। दक्षिण अफ्रीका के पास एक बिंदु लक्ष्य नहीं है - यह 3 से 6 प्रतिशत की मुद्रास्फीति लक्ष्य सीमा का अनुसरण करता है। चीन ने मुद्रास्फीति लक्ष्य को नहीं अपनाया है लेकिन मुद्रास्फीति को कम और स्थिर 3 प्रतिशत से नीचे रखता है। उन सभी ने बड़ी दर में कटौती और आरक्षित निधि आवश्यकता में कटौती के साथ महामारी से निपटा। अभी हाल ही में, ब्राजील और रूस ने नीतिगत समायोजन के सामान्यीकरण को पूरा कर लिया है और ब्राजील रूढ़िवादी सख्ती में है। भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने उदार मौद्रिक नीति रुख बनाए रखा है।

ब्रिक्स के बीच एक और आम विशेषता बड़ी राजकोषीय प्रोतत्साहन और अतिरिक्त खर्च और/या कर राजस्व को छोड़ देने के रूप में उनकी महामारी के संदर्भ में कार्रवाई रही है। परिणामस्वरूप, महामारी के कारण सकल राजकोषीय घाटा/जीडीपी अनुपात के संदर्भ में राजकोषीय स्थिति और खराब हो गई। महामारी से पहले रूस के पास राजकोषीय अधिशेष था और इसलिए उसके पास राजकोषीय गुंजाइश थी जिसका उपयोग महामारी के दौरान वित्तीय खातों पर कम से कम दबाव के साथ किया जा सकता था। तदनुसार, जीडीपी के 66 (चीन) - 99 (ब्राजील) प्रतिशत की सीमा में कर्ज-जीडीपी अनुपात के साथ राजकोषीय जोखिम तेजी से बढ़े हैं। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, रूस एक अलग देश है, जिसका जीडीपी की तुलना में कर्ज अनुपात सकल घरेलू उत्पाद के 20 प्रतिशत से कम है।

ब्रिक्स के लिए मध्यम अवधि की चुनौतियां जलवायु जोखिमों और उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं के संदर्भ में उत्पन्न होती हैं, जो ऊर्जा की कमी, प्रौद्योगिकी अंतराल को जन्म दे सकती हैं और इस तरह, मध्यम अवधि की संवृद्धि और मुद्रास्फीति के लिए जोखिम पैदा कर सकती हैं, खासकर बड़े कुल उत्सर्जन वाले देशों के लिए। भारत जैसे निवल आयातकों के लिए कमोडिटी की ऊंची कीमतों से एक और तत्काल चुनौती उत्पन्न होती है, हालांकि वे ब्राजील और रूस जैसे निवल निर्यातकों के लिए व्यापार की शर्तों (टीओटी) का लाभ प्रदान करते हैं। सभी ब्रिक्स देशों के लिए, प्राकृतिक आपदाओं और महामारी के कारण मांग-आपूर्ति असंतुलन के कारण खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों में मुद्रास्फीति का जोखिम बढ़ गया है।

ब्रिक्स के भीतर, प्रति व्यक्ति आय का स्तर व्यापक रूप से भिन्न है। भारतीय रिज़र्व बैंक के उत्कृष्टता केंद्र कैफरल (सीएएफ़आरएएल) में किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि प्रति व्यक्ति आय सभी तीन बाहरी रेटिंग एजेंसियों (एस एंड पी; मूडीज़; फिच) में क्रेडिट रेटिंग का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। सभी ब्रिक्स मध्यम-आय के फंदे की चपेट में हैं, जो एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें वे बढ़ती लागत और घटती प्रतिस्पर्धा के कारण उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था में संक्रमण करने में विफल

हो सकते हैं। मध्यम-आय वाली अर्थव्यवस्था को उच्च-आय वाली अर्थव्यवस्था में ले जाने के लिए निवेश और नवाचार दो प्रमुख तत्व हैं, और हमारी अर्थव्यवस्थाओं में उनमें से प्रत्येक को प्रभावित करने वाले समष्टि-आर्थिक कारकों को समझना आवश्यक है।

उपलब्धियां और सुपुर्दगी

वर्ष 2009-10 में ब्रिक्स के अस्तित्व में आने के बाद से, उनकी यात्रा महत्वपूर्ण पड़ावों से गुजरी है।

- **न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी)** ने वर्ष 2015 में काम करना शुरू किया और अपने सदस्य देशों में परिवहन, पानी और स्वच्छता, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल बुनियादी ढांचे, सामाजिक बुनियादी ढांचे और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में 30 बिलियन अमरीकी डालर के पोर्टफोलियो से जुड़ी लगभग 80 परियोजनाओं को मंजूरी दी। सितंबर 2021 से, एनडीबी नए सदस्यों (उरुग्वे; संयुक्त अरब अमीरात; बांग्लादेश) को मंजूरी दे रहा है। एनडीबी ने कोविड से संबंधित सहायता के लिए 10 बिलियन अमरीकी डालर का लक्ष्य रखा है, जिसमें से 7 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक का संवितरण पहले ही किया जा चुका है।
- **आकस्मिक आरक्षित निधि व्यवस्था या सीआरए** भुगतान संतुलन संकट के दौरान अल्पकालिक स्वैप सहायता प्रदान करने के लिए कुल 100 बिलियन अमरीकी डॉलर के साथ एक तंत्र है। स्वैप में 30 प्रतिशत का एक अलग हिस्सा होता है जिसे आपातकालीन चलनिधि सहायता और 70 प्रतिशत के एक जुड़े हिस्से के रूप में बढ़ाया जा सकता है, जो अनुरोध करने वाले वैसे देश पर आकस्मिक हैन जहां आईएमएफ कार्यक्रम चल रहा हो।
- **ब्रिक्स रणनीतिक आर्थिक साझेदारी वर्ष 2021-2025** व्यापार और निवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्था और संधारणीय विकास पर ध्यान देने के साथ सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग के लिए एक रोडमैप प्रदान करती है।
- **ब्रिक्स या ब्रिक्स सूचना सुरक्षा चैनल** वर्ष 2020 में रूस के राष्ट्रपति पद के दौरान शुरू की गई एक हालिया पहल है, जिसमें साइबर सुरक्षा और साइबर से संबंधित घटनाओं पर सूचना के आदान-प्रदान पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- **सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) और बुनियादी ढांचे संबंधी ब्रिक्स कार्यबल** बुनियादी ढांचे में सहयोग से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए एक मंच स्थापित करने की एक और पहल है। वर्ष 2021 में, सामाजिक बुनियादी ढांचे (स्वास्थ्य, शिक्षा) पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- **ब्रिक्स पेमेंट्स टास्क फोर्स (बीपीटीएफ़)** सीमा पार से भुगतान के प्रस्ताव सहित भुगतान प्रणाली में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्रीय बैंक की पहल है।
- **ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल** को ब्रिक्स के व्यापारिक समुदायों के बीच व्यापार, व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए एक मंच के रूप में बनाया गया है और यह सुनिश्चित करता है कि ब्रिक्स देशों की सरकारों और उनके बीच नियमित संवाद हो।
- **ब्रिक्स महिला व्यापार गठबंधन (डब्ल्यूबीए)** का उद्देश्य ब्रिक्स देशों में महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ावा देना है।
- **ब्रिक्स अकादमिक फोरम (बीएएफ)** ब्रिक्स देशों के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के बीच विचार-विमर्श और चर्चा के लिए एक मंच है, जो कई सामाजिक, पर्यावरणीय और शैक्षिक मुद्दों पर विचार और समाधान की कोशिश करता है।
- **ब्रिक्स थिंक टैंक काउंसिल (बीटीटीसी)** की शुरुआत वर्ष 2013 में ब्रिक्स देशों के अकादमिक समुदायों के बीच अनुसंधान और क्षमता निर्माण में सहयोग बढ़ाने के लिए की गई थी।
- **ब्रिक्स ऊर्जा अनुसंधान सहयोग प्लेटफॉर्म** ऊर्जा आधारित संधारणीय विकास, उन्नत ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को साझा करने, शैक्षिक कार्यक्रमों पर

सहयोग के विस्तार, राष्ट्रीय ऊर्जा प्रणालियों के विकास संबंधी सांख्यिकीय डेटा और योजनाओं के आदान-प्रदान और ऊर्जा क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं और नियामक ढांचे की जानकारी को बढ़ावा देता है। मंच का उद्देश्य विभिन्न प्लेटफार्मों में ब्रिक्स ऊर्जा सहयोग में तालमेल बनाना भी है।

- **ब्रिक्स एनवायरनमेंटली साउंड टेक्नोलॉजी (बीईएसटी) प्लेटफॉर्म**, वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के संधारणीय विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध प्रथाओं और पर्यावरण के अनुकूल ("हरित") प्रौद्योगिकियों से संबंधित अनुभव/सूचनाओं के संचय और आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करना है।
- **डिजिटल वित्तीय समावेशन संबंधी रिपोर्ट** डिजिटल प्रौद्योगिकी उपकरणों का लाभ उठाकर वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में ब्रिक्स देशों में की गई पहलों, नवाचारों और सुधारों को एक साथ रखती है। रिपोर्ट में डिजिटल वित्तीय समावेशन पर जी-20 उच्च-स्तरीय नीति दिशानिर्देशों के मुक़ाबले इन प्रयासों का भी चित्रण किया गया है।

भारत की अध्यक्षता में, छह परियोजनाओं को पहले ही पूरा करने के लिए आगे बढ़ाया जा चुका है:

- **सूचना सुरक्षा विनियमनों पर ई-बुकलेट और सूचना सुरक्षा जोखिमों पर ब्रिक्स की सर्वोत्तम प्रथाओं का संग्रह** साइबर घटना प्रबंधन प्रणालियों को मजबूत करने के उद्देश्य से ब्रिक्स अधिकार क्षेत्र में सूचना सुरक्षा नियमों और सर्वोत्तम प्रथाओं को कवर करता है।
- **सीआरए मूल्यांकन रिपोर्ट** में इस साल के सीआरए टेस्ट रन के साथ-साथ वर्ष 2018 के बाद से किए गए पिछले टेस्ट रन से उत्पन्न सभी मुद्दों और सिफारिशों को शामिल किया गया है।
- प्रथम **ब्रिक्स सहयोगात्मक अध्ययन 'कोविड-19: ब्रिक्स के भुगतान संतुलन के लिए प्रतिकूल और अनुकूल परिस्थितियां'** में वैश्विक स्तर पर और ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं में महामारी के कारण हुए गंभीर आर्थिक व्यवधानों पर प्रकाश डाला गया है, जिसके परिणामस्वरूप तेज चालू खाता समायोजन के साथ-साथ पूंजी प्रवाह में अस्थिरता हुई है।
- वर्ष 2021 के लिए **ब्रिक्स आर्थिक बुलेटिन** का विषय **'चल रही महामारी से निपटना: सुदृढ़ता और बहाली का ब्रिक्स अनुभव'** है। इसमें अलग-अलग आर्थिक सुधार, मुद्रास्फीति जोखिम, राजकोषीय दबाव, बाह्य क्षेत्र का प्रदर्शन और वित्तीय क्षेत्र की कमजोरियां शामिल हैं।
- वर्ष 2021 में, सीआरए के आईएमएफ से जुड़े हिस्से का परीक्षण पहली बार किया गया था। आईएमएफ के साथ सहयोग के तौर-तरीकों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
- शेष वर्ष में डिलिवरेबल्स में, **ब्रिक्स बॉन्ड फंड (बीबीएफ)**, जो सदस्य देशों में स्थानीय बॉन्ड बाजारों को विकसित करने की दृष्टि से ब्रिक्स केंद्रीय बैंकों की एक संयुक्त पहल है, अब पूरा होने के करीब है।
- ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों (एफ़एमसीबीजी) ने अगस्त 2021 में **'वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण और कोविड-19 संकट पर प्रतिक्रिया संबंधी एक ब्रिक्स वक्तव्य'** अपनाया। वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों ने ब्रिक्स सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रयास जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। महामारी के बाद की दुनिया में संधारणीय, संतुलित और समावेशी आर्थिक विकास और महामारी के लिए घरेलू आर्थिक प्रतिक्रियाओं पर ब्रिक्स देशों द्वारा नीतिगत अनुभवों को साझा करने का स्वागत किया।
- **एमएसएमई गोलमेज 2021** ने एमएसएमई के विकास की दृष्टि से ब्रिक्स सहयोग को बढ़ाने में मदद की है, जिससे उन्हें वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत किया जा सके।

- वर्ष 2021 में, **सीमा शुल्क मामलों में सहयोग और पारस्परिक प्रशासनिक सहायता पर ब्रिक्स समझौते** को अंतिम रूप दिया गया था।

अध्यक्ष के समक्ष चुनौतियां

अब मैं ब्रिक्स की अध्यक्षता के वर्ष में भारत के सामने आने वाली चुनौतियों की ओर आता हूं।

जीडीपी वृद्धि व्यापक रूप से किसी देश की आर्थिक प्रगति के संकेतक के रूप में उपयोग की जाती है। यदि कोई पिछले 75 वर्षों में पीछे मुड़कर देखता है, तो बाई-पेरॉन संरचनात्मक विराम बिंदु परीक्षण से पता चलता है कि भारत की वृद्धि प्रक्षेपवक्र तीन चरणों से गुजरी है। 1970 के दशक के अंत तक, भारत ने 3.5 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि की औसत प्रवृत्ति - तथाकथित हिंदू वृद्धि दर - जो उस अवधि में अपनाई गई आवक-दिखने वाली नीतियों से जुड़ी रही है। उदारीकरण और खुलेपन के रूप में वर्ष 1980-2002 के दौरान रुझान वृद्धि 5.5 प्रतिशत तक बढ़ गई। इसके बाद, वर्ष 2003-20 की अवधि में महामारी के आने तक जीडीपी की वृद्धि औसतन 7 प्रतिशत के करीब पहुंच गई। वर्ष 2020-21 में, जीडीपी में 7.3 प्रतिशत की गिरावट आई, जो उस वर्ष दुनिया भर में सबसे गहरे संकुचनों में से एक था।

भारत में संवृद्धि के वाहक क्या हैं? यह पता चला है कि भारत की वृद्धि हाउसहोल्ड्स - निजी उपभोग व्यय के कारण हुई है - हालांकि जीडीपी में इसकी हीसेदारी 1960 के दशक में 75 प्रतिशत से कम होकर हाल के वर्षों में लगभग 55 प्रतिशत हो गयी है। निर्यात-आधारित और निवेश-आधारित संवृद्धि के चरण ऐसे रहे हैं, जिन्हें कायम नहीं रखा जा सकता था, लेकिन उन्होंने वृद्धि पथ में महत्वपूर्ण मोड़ प्रदान किए।

भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स द्वारा इतनी मेहनत से बनाए गए क्लेम्स[2] (केएलईएमएस) डेटाबेस से पता चलता है कि भारत की संवृद्धि में पूंजी संचय सबसे बड़ा योगदानकर्ता है, जो लगभग 60 प्रतिशत है। इसलिए, निवेश दर (कुल निवेश/जीडीपी) को भारत में वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण उत्तोलक माना जाता है। एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि हमारी वृद्धि घरेलू है - निवेश को मुख्य रूप से घरेलू बचत द्वारा वित्तपोषित किया जाता है, जिसमें विदेशों से पूंजी प्रवाह केवल एक पूरक भूमिका निभाता है। एक और उल्लेखनीय विशेषता यह है कि वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) के बाद बचत दर धीमी होने लगी है। आखिरकार, इसने वर्ष 2012-13 से निवेश दर को नीचे ला दिया। उच्च वृद्धि हासिल करने के लिए इस प्रवृत्ति को उलटना महत्वपूर्ण है।

बीओपी (एक्स-एम) में चालू खाता घाटा (सीएडी) यह निर्धारित करता है कि देश में कितने निवल पूंजी प्रवाह को अवशोषित किया जा सकता है या संवृद्धि के लिए उपयोग किया जा सकता है। हमारा अनुभव रहा है कि भारत बाह्य क्षेत्र के संकट में पड़े बिना 2.5-3.0 प्रतिशत के चालू खाते के घाटे को बनाए रख सकता है। वास्तव में, इस तथ्य की एक याद दिलाने में, सोने के आयात में रिकॉर्ड वृद्धि ने वर्ष 2011-13 के दौरान इस प्लिमसोल लाइन से ऊपर चालू खाता घाटा ऐतिहासिक रूप से उच्च स्तर पर चला गया। भारत को टेपर टैंट्रम का सामना करना पड़ा और उसे नाजुक पांच[3] में से एक के रूप में लेबल किया गया।

2000 के दशक में लगभग 20 प्रतिशत की प्रभावशाली औसत निर्यात वृद्धि के बाद, जो व्यापार और वित्त के लिए अर्थव्यवस्था के खुलेपन में वृद्धि और जीडीपी की रुझान वृद्धि में उछल के साथ मेल खाता था, निर्यात वृद्धि वर्ष 2015 के बाद से गिर गई। बढ़ते व्यापार संरक्षणवाद ने अपना असर डाला, और यह अवधि जीडीपी वृद्धि दर में गिरावट के साथ भी जुड़ी हुई है। वर्ष 2021 में विश्व व्यापार में अब तक की मजबूत रिकवरी ने अपने साथ निर्यात के बारे में एक नए सिरे से आशावाद की भावना को फिर से संवृद्धि के इंजन के रूप में काम किया है। भारत का निर्यात वर्ष 2021-22 के लिए निर्धारित 400 बिलियन अमरीकी डॉलर के वार्षिक लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। वर्ष 2021-22 की पहली छमाही में, वास्तविक निर्यात स्तर पहले से ही लक्ष्य का आधा था। उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना जैसे उपायों से निर्यात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।[4] व्यापार के खुलेपन के

[2] केएलईएमएस से आशय पूंजी, श्रम, ऊर्जा, सामग्री और सेवाओं से है। यह ग्रोथ अकाउंटिंग फ्रेमवर्क पर आधारित है।

[3] ब्राजील, भारत, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की।

[4] घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और आयात बिलों में कटौती करने के लिए, केंद्र सरकार ने मार्च 2020 में एक पीएलआई योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य घरेलू इकाइयों में निर्मित उत्पादों से वृद्धिशील बिक्री पर कंपनियों को प्रोत्साहन देना है।

अनुरूप वित्तीय खुलेपन में भी सुधार हो रहा है - भारत ने वैश्विक प्रवृत्ति को पीछे छोड़ दिया और वर्ष 2020-21 में 82 बिलियन अमरीकी डॉलर के उच्चतम आवक एफडीआई दर्ज किया।

भारत में बैंक के नेतृत्व वाली वित्तपोषण प्रणाली है और इसलिए, बैंक ऋण वृद्धि संवृद्धि के लिए वित्तपोषण चुनौतियों का एक बेहतर संकेतक है। हाल के वर्षों में - 2017 के बाद से - बैंक ऋण में मंदी आई है, विशेष रूप से उद्योग के लिए। यह काफी हद तक अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के एक बड़े ओवरहैंग के कारण बैंकों के तुलन-पत्र में तनाव के कारण है, जो 2000 के दशक के मध्य में ऋण उछल के कारण हुआ था। वैश्विक अति-क्षमता और अर्थव्यवस्था की मंदी के कारण निवेश चक्र में बदलाव आया, परियोजना में देरी हुई और लागत में वृद्धि हुई। बैंक चूक में वृद्धि हुई, और दबावग्रस्त बैंक नए ऋण जोखिम लेने के लिए अनिच्छुक हो गए। इसके अलावा, जीएफसी के बाद में, बैंकों को आस्तियों के पुनर्गठन और उन्हें 'मानक' अग्रिम के रूप में मानने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अतिरिक्त प्रावधानों के साथ। अप्रैल 2015 से अग्रिमों की पुनर्रचना पर विनियामकीय सहनशीलता को वापस लेने और बाद में आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) के कारण सकल एनपीए (जीएनपीए) की अधिक यथार्थवादी पहचान हुई। मार्च 2018 में 11.5 प्रतिशत के शिखर पर पहुंचने के बाद जीएनपीए अनुपात में गिरावट आई है, जिसका मुख्य कारण दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) प्रक्रिया के तहत दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान और दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए रिज़र्व बैंक के संशोधित ढांचा है। कोविड-19 की शुरुआत से पहले, भारत में जीएनपीए अनुपात मार्च 2020 के अंत में 8.3 प्रतिशत था। यह मार्च 2021 के अंत तक 7.5 प्रतिशत तक गिर गया, जो यह दर्शाता है कि बैंकों ने महामारी की अवधि का उपयोग वसूली में सुधार के लिए किया था और अपनी तुलन-पत्र में उच्च प्रावधान करते हुए अचूक ऋणों को बट्टे खाते में डाला। बैंकों के जोखिम से बचने की स्थिति में, गैर-बैंकिंग स्रोत (घरेलू और विदेशी दोनों) हाल के वर्षों में भारत के वाणिज्यिक क्षेत्र में संसाधनों के प्रवाह में उतना ही या उससे भी अधिक योगदान दे रहे हैं।

आपूर्ति में व्यवधान, स्वास्थ्य संकट, अद्वितीय सामूहिक प्रवास और प्रतिकूल वैश्विक वातावरण के कारण उत्पादन का काफी नुकसान हुआ है – जो एक सामान्य वर्ष के वार्षिक जीडीपी के दसवें हिस्से से अधिक है। वर्ष 2021-22 में (भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमानों के अनुसार) 9.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ, भारत की जीडीपी वर्ष 2019-20 में अपने स्तर से ऊपर होगी। इस खोए हुए उत्पादन को पुनर्प्राप्त करने में कई साल लग सकते हैं - इसे मैं दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चुनौती मानूंगा। इससे पहले मैंने ब्रिक्स के संदर्भ में कहा था कि पूरी आबादी का त्वरित टीकाकरण सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है।

श्रम ब्यूरो के अप्रैल 2021 के तिमाही रोजगार सर्वेक्षण (क्यूईएस) में 9 क्षेत्रों और 85 प्रतिशत संगठित क्षेत्र के रोजगार को शामिल किया गया है, जो यह दर्शाता है कि 21 मार्च 2020 और 1 जुलाई 2020 के बीच, यानी लॉकडाउन अवधि में, सभी क्षेत्रों में कर्मचारियों की संख्या में गिरावट का सामना करना पड़ा। स्वास्थ्य और वित्तीय क्षेत्रों को छोड़कर, केवल 34 प्रतिशत इकाइयाँ 25 मार्च 2020 से 30 जून 2020 के दौरान कार्य कर सकीं। वेतन हानि के संबंध में, संगठित क्षेत्र पर प्रभाव नरम था क्योंकि 80.7 प्रतिशत कर्मचारियों को पूर्ण वेतन मिला और केवल 2.7 प्रतिशत बिना वेतन के चले गए। लोगों को काम पर वापस लाना, बदलते परिवेश का सामना करने के लिए उन्हें फिर से कुशल बनाना और उनकी उत्पादकता को बढ़ाना तीसरी चुनौती है। 132 देशों में से भारत श्रम उत्पादकता के मामले में 100वें स्थान पर है।

भारत की 1.38 अरब की आबादी 28.4 वर्ष में दुनिया की सबसे युवा आबादी है, लेकिन उम्र बढ़ने से 2045 तक जनसांख्यिकीय लाभांश खत्म हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या संभावनाओं के अनुसार, वर्ष 2027 तक, भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश (1.47 बिलियन) होगा। जनसंख्या की इस संरचना को आयु निर्भरता अनुपात द्वारा बेहतर तरीके से दर्शाया जा सकता है - कुल कामकाजी-आयु की आबादी के अनुपात में आश्रित जनसंख्या (0-14 वर्ष और 65+ वर्ष) का अनुपात: अनुपात के कम मान का अर्थ अधिक उत्पादक आबादी से है। भारत का आयु निर्भरता अनुपात घट रहा है और वर्ष 2025 तक इसमें और गिरावट आने की संभावना है जिसके बाद यह वर्ष 2040 तक स्थिर रह सकता है और उसके बाद बढ़ सकता है। कुल जनसंख्या या डबल्यूएपी अनुपात के अनुपात के रूप में भारत की कामकाजी उम्र की आबादी की तुलना से पता चलता है कि भारत एक लाभप्रद स्थिति में है - भारत का डब्ल्यूएपी अनुपात

वर्ष 2045 तक बढ़ जाएगा, भले ही यह दुनिया में कहीं और घट रहा हो। इस जनसांख्यिकीय लाभांश का अधिकतम लाभ उठाना भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने चौथी बड़ी चुनौती है।

वर्ष 2013 में भारत नाजुक पांच देशों में से एक था क्योंकि बाह्य क्षेत्र की व्यवहार्यता टेपर टैंट्रम के दौरान बिगड़ गई थी। वर्ष 2013 में समष्टि-आर्थिक विन्यास के सापेक्ष, भारत वर्तमान में बेहतर स्थिति में है क्योंकि इसके समष्टि-आर्थिक के मूल तत्वों में काफी सुधार हुआ है और बाह्य क्षेत्र के संकेतक बाहरी झटकों को प्रबंधित करने के लिए पर्याप्त कुशन की उपलब्धता की ओर इशारा करते हैं। मैं इस ताकत को एक चुनौती के रूप में प्रस्तुत करता हूं क्योंकि भू-राजनीतिक तनावों, कोविड के लंबे समय तक रहने वाले असर और जलवायु परिवर्तन की अनिवार्यता के साथ अंतरराष्ट्रीय वातावरण प्रतिकूल हो रहा है। इसके अलावा, दुनिया भर के देश अपने नीतिगत रुख को एक महामारी मोड से दूर एक सामान्य स्थिति में ले जाने पर विचार कर रहे हैं। इसमें वैश्विक प्रभाव विसरण शामिल होंगे जिससे भारत अछूता नहीं कर सकता है। इसलिए बाह्य क्षेत्र की व्यवहार्यता महत्वपूर्ण है।

भारत वर्तमान में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। क्रय शक्ति समता (पीपीपी) की दृष्टि से भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अनुमानों से पता चलता है कि वर्ष 2040 तक भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मेरे विचार से यह अंतिम चुनौती है - ब्रिक्स के साथ मिलकर वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने की तैयारी करना।

धन्यवाद।